नईदुनिया e-paper

Image View | Text View | Comment | Email | Print

Published in 06 Jan-2012 | Print Edition of Naidunia

एक व्हीकल की कीमत एक से तीन करोड़ रुपए

मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल की नजर रहेगी भीड़ पर!

फाइल फोटो

रामकुमार भारती भोपाल

कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश पुलिस भी प्रदेश में होने वाले धरना- प्रदर्शन, रैली और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर अब मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल से नजर रखेगी। इस व्हीकल में कई ऐसे आधुनिक उपकरण लगे हैं, जो वायरलेस कैमरे की मदद से दो सौ मीटर के क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे दो मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल खरीदने का निर्णय किया है।

दरअसल प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले बड़े कार्यक्रमों में पुलिस की लंबी-चौड़ी फौज लगा दी जाती है। बावजूद इसके कई बार अप्रिय वारदात होने की आशंका बनी रहती है। लिहाजा ऐसे कार्यक्रमों पर मोबाइल कमांड कं ट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सिस्टम के जरिए बनाए गए मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल से नजर रखी जा सकती है। इस वाहन को कहीं भी खड़ा किया जा सकता है तथा इस का निर्माण बैंगलोर की मिस्ट्राल सोलुशन नामक कंपनी ने किया है। यह कंपनी होमलैंड सिक्यूरिटी के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रही है। इस कंपनी ने कई अलग-अलग वाहन बनाए हैं, जिसकी कीमत एक से तीन करोड़ के बीच है। ऐसे दो वाहन खरीदने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ऑर्डर दे दिए हैं।यह वाहन अभी देश में केवल गुजरात और कर्नाटक पुलिस के पास ही है।

■ गुजरात की तर्ज पर मप्र पुलिस भी खरीदेगी वाहन

पीएचक्यू में तकनीकी प्रदर्शन

पुलिस मुख्यालय ने बैंगलोर की मिस्ट्राल सोलुशन नामक कंपनी के अधिकारियों को तकनीकी प्रदर्शन के लिए मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल लेकर भोपाल बुलाया था। कंपनी के अधिकारी गुरुवार को बैंगलोर से मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल लेकर आए और पीएचक्यू में कई स्थानों पर वायरलेस कैमरे लगा दिए। इस कैमरे के जरिए काफी देर तक हर गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसे इंटेलीजेंस और एटीएस के अफसरों ने काफी देर तक देखा और इसकी तकनीक की सराहना की।

“ प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों पर मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल से नजर रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने दो वाहन खरीदने का निर्णय किया है। इस व्हीकल में लगे कैमरे की मदद से कार्यक्रम की हर गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है।

-एसके पांडे, आईजी कानून-व्यवस्था ”